भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3134

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस की कुशलता और ईपीओएस मशीनों से जुड़ी समस्याएं

3134. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दक्षता बढ़ाने के लिए, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों में बार-बार होने वाली तकनीकी खामियों और डाउनटाइम के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीओएस मशीन की विफलताओं के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कितनी है और लाभार्थियों के लिए निर्बाध आधार-समर्थित प्रमाणीकरण और बायोमीट्रिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों में बार-बार आने वाली तकनीकी खराबी और डाउनटाइम को दूर करने के लिए, जब भी राज्य सरकारों द्वारा ऐसी समस्याओं की रिपोर्ट की जाती है, तो यह विभाग राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के समक्ष मामले को उठाता है और उनके समन्वय से इसका समाधान करता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों में ई-पीओएस मशीन की खराबी के संबंध में दर्ज शिकायतों की कोई राज्यवार रिपोर्ट इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं, तकनीकी कारणों, आधार लिंकिंग संबंधी समस्याओं या खराब बायोमेट्रिक गुणवत्ता के कारण बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणीकरण में विफलता होने पर किसी भी लाभार्थी या परिवार को सब्सिडी वाले उनके पात्र खाद्यान्न की मात्रा से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक और अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करें।

*****